PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

**Amar Ujala, Delhi**
**Thu, 25 May 2017, Page 21**
**Width: 50.16 cms, Height: 71.24 cms, a3, Ref: 21.2017-05-25.173**

*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मिथकों को तोड़ा है, तो कई नए मिथक भी सृजित किए हैं। देश की जनता में सपनों को हकीकत में ढालने का जोरदार जज्बा पैदा किया है। वहीं धरातल पर अभी कई पायदान नाप कर लक्ष्य हासिल करने की चुनौती भी कायम है। तीसरा साल पूरा होने पर उन्हीं का आकलन पेश है-*

# गहरा रहा सुधारों का रंग आहिस्ता-आहिस्ता

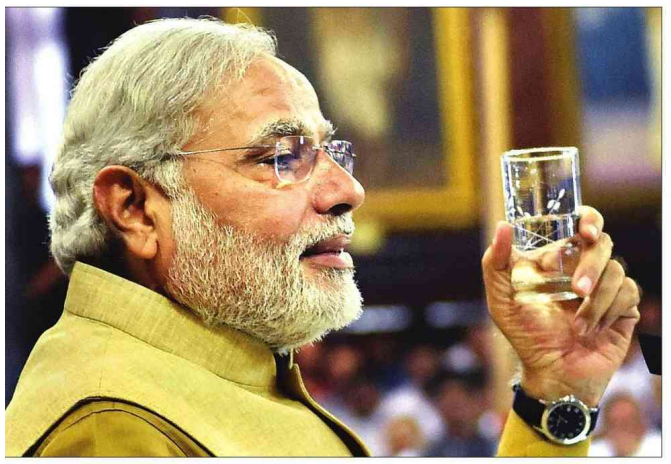

**मधु पूर्णिमा किश्वर**
**प्रोफेसर, आईसीएसएसआर एवं सामाजिक कार्यकर्ता**

तीन साल के कार्यकाल में नोटबंदी को मोदी सरकार का सबसे साहसिक फैसला कहा जा सकता है। यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था और इसने पूरे विपक्ष को अवाक कर दिया। चूंकि इसे काले धन और आतंकी फंडिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में पेश किया गया, जिससे यह संदेश गया कि नोटबंदी का विरोध वही पार्टियां या नेता कर रहे हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति जमा कर रखी है। यह दुखद है कि इस कदम पर खुली और गंभीर बहस नहीं हो सकी। यह हैरान करने वाला था कि भारी असुविधाओं के बावजूद आम लोगों ने इसे काले धन के सफाये के दृढ़ संकल्प का सबूत माना।

**सबसे सकारात्मक पहलू**

**आधारभूत संरचनाः** नितिन गडकरी को मोदी मंत्रिमंडल का सबसे चमकता सितारा कहा जा सकता है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। सड़क, पुल, बंदरगाह और जल परिवहन के विकास के लिए बहुत सारे मंत्रालयों और विभागों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है और उनकी मंजूरी लेनी होती है। आज देश में रोजाना 23 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है और उसकी गुणवत्ता भी बेहतर हुई है। ये सड़कें कागजों पर नहीं हैं, जैसा कि पहले हुआ करती थीं। ये पक्की सड़कें हैं, जिनकी वजह से यात्रा सुरक्षित हुई है और सफर का समय भी बचता है। हालांकि रेल नेटवर्क का विस्तार इस गति से नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु में इच्छाशक्ति की कमी है, बल्कि इसलिए कि संसाधनों की कमी है। गडकरी की तुलना में उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि रेल किराये में बढ़ोतरी राजनीतिक हमलों को न्यौता दे सकती है। अफसोस कि एक ओर तो हम विश्वस्तरीय सड़क निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर हमारी ट्रेनें सुरक्षा, गुणवत्ता और यात्री सुविधा के लिहाज से फिसड्डी हैं। रेलवे को भारत की जीवन रेखा के रूप में अपनी भूमिका को व्यापक करना चाहिए।

**ऊर्जा क्षेत्र में सुधारः** निश्चित समयसीमा के भीतर हर घर और हर गांव तक बिजली पहुंचाने की प्रतिबद्धता, ताकि यह सिर्फ कोरा वायदा न रह जाए। रिकॉर्ड समय के भीतर देश में सरप्लस बिजली हो गई है। सक्षम प्रौद्योगिकी के जरिये बिजली की लागत और चोरी घटी है। पवन और सौर ऊर्जा जैसे पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन चुका है। व्यापक रूप में बिजली की बचत करने वाले उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खुद मोदी इस ओर जोर दे रहे हैं, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इन उपायों को अपनाया था।

**गरीबों के घरों में रसोई गैसः** मोदी सरकार ने तेजी से गरीब लोगों के घरों तक सस्ती रसोई गैस पहुंचाई है, ताकि गरीब महिलाओं को धुएं, लकड़ी इकट्ठा करने और मिट्टी के चूल्हों से निजात मिल सके, वह वाकई दिल को छू लेने वाला है।

## विदेश नीति

व्यक्तिगत तौर पर मोदी की सबसे बड़ी कामयाबी विदेश नीति के क्षेत्र में देखी जा सकती है। जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब पश्चिम के कई देशों और अरब जगत ने उन पर प्रतिबंध तक लगा दिया था, मगर उन्होंने चमत्कारिक ढंग से अंतरराष्ट्रीय राय को न केवल अपने पक्ष में, बल्कि भारत के पक्ष में पलट दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान को छोड़कर इस्लामिक जगत तक में उनकी गिनती दुनिया के बड़े राजनेताओं के रूप में होती है।

## आंतरिक सुरक्षा

वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने तक को राजी हो जाने वाली ज्यादातर विपक्षी पार्टियों की तुलना में मोदी इस मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं करते, जबकि शुरू में अलगाववादियों और पाकिस्तान के प्रति उनका रुख कुछ नरम लग रहा था। मोदी सरकार अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में अधिक आक्रमक हो सकती है, क्योंकि राज्यसभा में वह पहले से बेहतर है और उत्तर प्रदेश और असम में बड़ी जीत से उसे ताकत मिली है।

*हर स्तर पर प्रतिभा आधारित पारदर्शी नियुक्ति की व्यवस्था कायम होनी चाहिए। मोदी सरकार की निष्पक्ष समीक्षा साफ दिखाती है कि केवल वही मंत्रालय और विभाग अच्छा काम कर रहे हैं, जहां सरकार ने समुचित प्रतिभाशाली व्यक्ति को नेतृत्व की जिम्मेदारी दी है। मगर कई मंत्रालय खराब ढंग से काम कर रहे हैं, क्योंकि गलत लोगों के हाथ में उनकी कमान है। मोदी को चाहिए कि वह हर मंत्रालय पर नजर रखने का लोभ छोड़ें और उसके बजाय भरोसमंद और ऐसे सक्षम लोगों का चयन करें, जो छोटे-छोटे निर्णयों के लिए भी प्रधानमंत्री की मंजूरी का इंतजार किए बिना खुद से निर्णय ले सकते हों।*